

उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भरती में अनुचित साधनों की रोकथाम व नविवरण के उपाय) अध्यादेश 2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

9 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिये उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भरती में अनुचित साधनों की रोकथाम व नविवरण के उपाय) अध्यादेश 2023 का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बंदि

■ इस अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान नमिनलखित हैं-

- इस अध्यादेश में दोषियों के वरिद्ध सख्त प्रावधान किये गए हैं। यदि कोई व्यक्ति, प्रैटिगि प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लपित पाया जाता है तो उसके लिये आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लपित पाया जाता है तो उसके लिये तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पाँच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि विद्यार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखल होने की तथिसे दो से पाँच वर्ष के लिये डबिार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिये समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डबिार किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः पाँच से दस वर्ष के लिये तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डबिार किये जाने का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जति संपत्त की कुरकी की जाएगी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।